



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 14, 2012/वैशाख 24, 1934

No. 125]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 14, 2012/VAISAKHA 24, 1934

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2012

दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (नौवां संशोधन) विनियम, 2012  
(2012 का 11)

सं. 305-24/2011-क्यूओएस (एसपी).—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के उप-खंड (वी) तथा खंड (सी) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (नौवां संशोधन) विनियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम, इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) के विनियम 18 के उप-विनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“बशर्ते कि यदि टेलीमार्केटर को प्रचारक संदेश भेजने के लिए आर्बिटित दूरसंचार संसाधन के माध्यम से अवाञ्छित वाणिज्यिक संप्रेषण भेजने के कारण ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो उसके प्रचारक संदेश भेजने हेतु आर्बिटित दूरसंचार संसाधनों को विच्छेदित (डिस्कनेक्ट) कर दिया जाएगा;

“बशर्ते आगे कि यदि टेलीमार्केटर को लेन-देन संदेश भेजने के लिए आवंटित दूरसंचार संशोधन के माध्यम से अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण भेजने के कारण ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो उसके लेन-देन एवं प्रचारक संदेश भेजने हेतु आवंटित दूरसंचार संसाधनों को विच्छेदित (डिस्कनेक्ट) कर दिया जाएगा।”

सुधीर गुप्ता, सचिव-कायंभारी

[विज्ञापन III/4/असाधारण/142/12]

टिप्पणी 1: मूल विनियम अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस दिनांक 1 दिसंबर 2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए।

टिप्पणी 2: मूल विनियम अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस दिनांक 14 दिसंबर 2010 के तहत संशोधित किए गए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए।

टिप्पणी 3: मूल विनियम अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस दिनांक 28 दिसंबर 2010 के तहत पुनः संशोधित किए गए (दूसरा संशोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए।

टिप्पणी 4: मूल विनियम अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस दिनांक 31 जनवरी 2011 के तहत पुनः संशोधित किए गए (तीसरा संशोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए।

टिप्पणी 5: मूल विनियम अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस दिनांक 28 फरवरी 2011 के तहत पुनः संशोधित किए गए (चौथा संशोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए।

टिप्पणी 6: मूल विनियम अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस दिनांक 18 मार्च 2011 के तहत पुनः संशोधित किए गए (पांचवां संशोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए।

**टिप्पणी 7:** मूल विनियम अधिसूचना संख्या 352-04/2011-सीए (क्यूओएस) पार्ट, दिनांक 05 सितम्बर, 2011 के तहत पुनः संशोधित किए गए (छठवां संशोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए।

**टिप्पणी 8:** मूल विनियम अधिसूचना संख्या 352-04/2011-सीए (क्यूओएस) दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 के तहत पुनः संशोधित किए गए (सातवां संशोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए।

**टिप्पणी 9:** मूल विनियम अधिसूचना संख्या 352-04/2011-सीए (क्यूओएस) दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के तहत पुनः संशोधित किए गए (आठवां संशोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए।

**टिप्पणी 10:** व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (नौवां संशोधन) विनियम, 2012 (2012 का 11) के उद्देश्यों एवं कारणों की व्याख्या दी गई है।

#### व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण पर रोक लगाने के लिए एक प्रभावी तंत्र का प्रावधान करने हेतु दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) (जिसे इसमें आगे मूल विनियम कहा गया है) दिनांक 1 दिसंबर 2010 को जारी किया। इन विनियमों के सभी उपबंध दिनांक 27 सितम्बर, 2011 से लागू हुए।
2. मूल विनियमों में यह उपबंध है कि प्रत्येक एक्सेस प्रदाता द्वारा लेन-देन एवं प्रचारक संदेश भेजने के लिए पृथक् दूरसंचार संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे तथा मूल विनियमों की अनुसूची-IV एवं अनुसूची- V के अनुसार क्रमशः प्रचारक या लेन-देन संसाधन उपलब्ध कराने से पूर्व अलग-अलग करार करना होगा।

3. मूल विनियमों में यह भी उपबंध है कि यदि राष्ट्रीय ग्राहक अधिमान रजिस्टर(एनसीपीआर) में पंजीकृत उपभोक्ता से अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण प्राप्त होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उद्भव एक्सेस प्रदाता द्वारा संबंधित टेलीमार्केटर को उसके द्वारा भेजी गई अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण(यूसीसी) विवरण का उल्लेख करते हुए नोटिस जारी किया जाएगा तथा उसे मूल विनियमों की अनुसूची-IV एवं अनुसूची- V की शर्तों की सहमति अनुसार प्रतिभूति जमा में से काटी गई धनराशि की सूचना भी दी जाएगी एवं किसी भी एक्सेस प्रदातां द्वारा यदि टेलीमार्केटर को अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण(यूसीसी) भेजने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में छह नोटिस दिए जाते हैं तो ऐसे टेलीमार्केटर का नाम दो वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा। टेलीमार्केटर के एक बार ब्लैकलिस्ट हो जाने पर, प्रत्येक एक्सेस प्रदाता द्वारा विनियमों के तहत ऐसे टेलीमार्केटर को उपलब्ध कराए गए दूरसंचार संसाधनों को विच्छेदित (डिस्कनेक्ट) किया जाएगा।

4. जहाँ तक दूरसंचार उपभोक्ताओं के लेन-देन संदेशों के महत्व का प्रश्न है, प्राधिकरण ने विचार किया है कि यदि प्रचारक संसाधनों के माध्यम से अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण के कारण टेलीमार्केटर को ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो, उसके द्वारा एक्सेस प्रदाता से लेन-देन संसाधनों सहित खरीदे गए सभी संसाधनों के विच्छेदित (डिस्कनेक्ट) किए जाने से उपभोक्ता को असुविधा होगी। तथापि, हालांकि, यदि प्रचारक संदेश भेजने के लिए लेन-देन पाइप का दुरुपयोग किया जाता है तो टेलीमार्केटर के दोनों अर्थात् प्रचारक संदेश एवं लेन-देन संदेश के दूरसंचार संसाधनों का विच्छेदित (डिस्कनेक्ट) किया जाएगा। जब भी टेलीमार्केटर को प्रचारक संसाधनों या लेन-देन संसाधनों के माध्यम से अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण भेजने के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो उसे, इन विनियमों के तहत ब्लैकलिस्ट अवधि के दौरान कोई भी दूरसंचार संसाधन प्राप्त नहीं होंगे। तदनुसार, प्राधिकरण द्वारा मूल विनियमों के विनियम 18 के उप-विनियम (5) में संशोधन किया गया है।

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2012

**The Telecom Commercial Communications Customer Preference  
(Ninth Amendment) Regulations, 2012**

(11 of 2012)

**THE TELECOM COMMERCIAL COMMUNICATIONS CUSTOMER  
PREFERENCE (NINTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2012  
(11 OF 2012)**

**No. 305-24/2011-QoS (SP).**—In exercise of powers conferred by section 36, read with sub-clause(v) of clause (b) and clause (c) of sub-section (1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations, namely:-

- 1.** (1) These regulations may be called the Telecom Commercial Communications Customer Preference (Ninth Amendment) Regulations, 2012.  
(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

- 2.** In regulation 18 of the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (6 of 2010), after sub-regulation (5), the following proviso shall be inserted, namely:-

*“Provided that in case the telemarketer is blacklisted for sending unsolicited commercial communications through the telecom resources allotted to it for sending promotional messages, the telecom resources provided to it for sending promotional messages shall only be disconnected;*

*Provided further that in case the telemarketer is blacklisted for sending unsolicited commercial communications through the telecom resources allotted to it for sending transactional messages, the telecom resources provided to it for sending*

1715 G.I/12-2

transactional messages and promotional messages shall be disconnected."

SUDHIR GUPTA, Secy.-in-charge

[ADVT. III/4/Exty./142/12]

Note 1: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification No. 305-17/2010-QoS dated 1<sup>st</sup> December, 2010.

Note 2: The principal regulations were amended vide notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 14<sup>th</sup> December, 2010.

Note 3: The principal regulations were further amended (second amendment) vide notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 28<sup>th</sup> December, 2010.

Note 4: The principal regulations were further amended (third amendment) vide notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 31<sup>st</sup> January, 2011.

Note 5: The principal regulations were further amended (fourth amendment) vide notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 28<sup>th</sup> February, 2011.

Note 6: The principal regulations were further amended (fifth amendment) vide notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 18<sup>th</sup> March, 2011.

Note 7: The principal regulations were further amended (Sixth amendment) vide notification No. 352-4/2011-CA (QoS) Pt. and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 05<sup>th</sup> September, 2011.

Note 8: The principal regulations were further amended (Seventh amendment) vide notification No. 352-4/2011-CA (QoS) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 25<sup>th</sup> October, 2011.

Note 9: The principal regulations were further amended (Eighth amendment) vide notification No. 352-4/2011-CA (QoS) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 1<sup>st</sup> November, 2011.

Note 10: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of Telecom Commercial Communications Customer Preference (Ninth Amendment) Regulations, 2012 (11 of 2012).

**EXPLANATORY MEMORANDUM**

1. The Telecom Regulatory Authority of India made the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulation, 2010 (6 of 2010) (hereinafter referred to as the principal regulations) dated the 1st December, 2010 to provide an effective mechanism for curbing unsolicited commercial communications. All the provisions of regulations came into force from 27<sup>th</sup> September 2011.
2. The principal regulations provide that every Access Provider shall provide separate telecom resources, for sending transactional message and promotional messages and has to enter into separate agreements before providing promotional or transactional resources in accordance with Schedule-IV and Schedule-V of the principal regulations, respectively.
3. The principal regulations also provide that in case of receipt of a complaint regarding the receipt of Unsolicited Commercial Communication by a subscriber who is registered on National Customer Preference Register (NCPR), the originating access provider shall issue a notice to the concerned telemarketer, forwarding the detail of the UCC made by him and informing him of the deduction made from the security deposit of an amount as agreed upon in terms of Schedule IV or Schedule V to the principal regulations and upon service of the sixth notice in a calendar year by any Access Provider on a telemarketer for sending UCC, the name of such telemarketer will be entered into the blacklist for two years. Once a telemarketer is blacklisted, every Access Provider shall disconnect the telecom resources provided by it under the regulations to such telemarketer.
4. With regards to the importance of transactional messages to the telecom consumers, the Authority considered that in case a telemarketer is blacklisted for sending Unsolicited

Commercial Communications through promotional resources, the disconnection of all the resources procured by him from Access Providers including the transactional resources would cause inconvenience to the consumers. However, in case the transactional pipe is misused to send promotional messages, the telecom resources of the telemarketer for both the promotional messages and transactional messages shall be disconnected. Whenever a telemarketer is blacklisted for sending Unsolicited Commercial Communications either through promotional resources or through transactional resources, it will not get any telecom resources under these regulations for the period of blacklisting. Accordingly, the Authority has amended sub-regulation (5) of regulation 18 of the principal regulations.